प्रकाशन का 41 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

www.facebook.com/shailshamachar

वर्ष 42 अंक – 17 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पर्जीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-17 सोमवार 24 – 1 मई 2017 मूल्य पांच रूपए

पीएमओ में हटा हाईड्रो कॉलिज की पट्टिका से जे.पी.नड्डा का नाम

शिमला/शैल। भाजपा की परिवर्तन रैली भाजपा के भीतर ही कई बदलावों के संकेत दे गयी है यह मानना है राजनीतिक विश्लेषकों का। और इस मानने का आधार है प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी द्वारा नड्डा के बिलासपुर में देश के पहलेहाईड्रो इंजीनियरिंग कॉलिज के उद्घाटन के अवसर पर वहां लगी पट्टिका। इस पट्टिका में प्रदेश के राज्यपाल, प्रदेश के मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल और मन्त्री जी.एस.बाली। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश सरकार ने इसके लिये केन्द्रिय स्वास्थ्य मन्त्री जेपी नड्डा के नाम की भी संस्तुति की थी क्योंकि नड्डा बिलासपुर जिले से ताल्लुक रखते हैं और मोदी के सहयोगी मन्त्री हैं तथा उन्हे प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री के रूप में भी देखा जा रहा है। परन्तु जब पीएमओ से इस पट्टिका पर लिखे जाने वाले नामों की सूची राज्य सरकार के पास पहुंची तो नड्डा का नाम इस सूची से गायब पाये जाने पर सब हैरान थे। नड्डा के इस प्रकरण के साथ ही पूर्व मुख्यमन्त्री एवम् पूर्व केन्द्रिय मन्त्री रहे शान्ता कुमार का इस रैली में जिन भी कारणों से भाषण नही हो सका उसके संकेत भी बहुत सकारात्मक नही रहे हैं।

फिर इस रैली से पूर्व नगर निगम शिमला की पूर्व मेयर रही मधु सूद अपने पति सहित कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुई। मधु सूद के अतिरिक्त कैलाश फैडरेशन के अध्यक्ष बृज लाल और उनके साथ सीता राम धीमान व गुरूदत्त शर्मा बगैरा भी भाजपा में शामिल हुए। पिछले काफी अरसे से यह क्यास लगाये जा रहे थे कि कांग्रेस के कुछ मन्त्री और विधायक भाजपा में शामिल हो सकते हैं। कई विधायकों/मन्त्रीयों के नाम तक खबरों में उछल गये थे। जब प्रधानमन्त्री शिमला आ ही रहे थे तो ऐसे लोगों को भाजपा में शामिल करवाने का इससे अच्छा मौका कोई और हो ही नही सकता था। प्रदेश को कांग्रेस मुक्त करने के लिये कुछ बड़े लोगों को इस अवसर पर भाजपा में शामिल करवाया जाना बनता था ताकि एक बड़ा संकेत और संदेश जाता। इससे कई दिनों तक प्रदेश के राजनीतिक पारे को गर्म रखा जा सकता था। लेकिन संयोग वश भाजपा यह सब नही कर पायी।

अभी नगर निगम शिमला के चुनाव होने जा रहे हैं। नगर निगम शिमला में इस दौरान एशियन विकास बैंक की ऋण सहायता से पर्यटन विभाग के तहत करीब 260 करोड़ का सौन्दर्यकरण का काम चल रहा है। इस काम को अंजाम देने में बतौर ठेकेदार अभी भाजपा में शामिल हुई पूर्व मेयर मधु सूद के पति पी.के. सूद की बड़ी भूमिका है। इस काम की गुणवता पर भाजपा के पूर्व प्रदेश और शिमला के विधायक सुरेश भारद्वाज स्वयं सवाल उठा चुके हैं। अभी निगम चुनावों में यह एक बड़ा मुद्दा होगा यह तय है। फिर नोटबंदी के दौरान लेवर के माध्यम से पुराने नोट मालरोड के बैंक से बदलवाने में भी कई चर्चाएं रही हैं। सूत्रों की माने तो आयकर विभाग की सूची में भी यह नाम पड़ताल के दायरे में आ चुके हैं। भाजपा में शामिल होने वाले इन सबके अपने-अपने कारण हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा प्रदेश कांग्रेस मुक्त करके साठ के आंकड़े को कैसे हालिस कर पाती है।

इस समय राष्ट्रीय स्तर पर जो लहर भाजपा के पक्ष में चल रही है। वह विधानसभा चुनावों तक कैसे बरकरार रह पाती है यह एक बड़ा सवाल होगा। क्योंकि अभी एमसीडी के चुनाव में जिन दो सीटों पर मतदान नही हो सका था अब वहां दो दिन बाद ही चुनाव में दोनों सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की जीत हुई है उसमें भी एक सीट उस राजौरी गार्डन की है जहां विधानसभा के उप-चुनाव में आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हुई थी। दो दिन में ही भाजपा की लहर का गाबय हो जाना यह इंगित करता है कि आम आदमी पार्टी ने ईवीएम मशीनों की विश्वसनीयता पर जो सवाल उठाये थे शायद उनमें कोई दम था। अब ईवीएम पर उठते इन्ही सवालों के कारण चुनाव आयोग ने हिमाचल सहित आने वाले हर चुनाव में VVPAT सिस्टम मशीनों के इस्तेमाल की घोशणा की है।

ऐसे में हिमाचल के आने वाले चुनावों में भ्रष्टाचार ही सबसे बड़ा मुद्दा होगा। इस मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व एक बराबर घिरा हुआ है। कौन किसको पहले अंजाम तक पहुंचाता है यह देखना शेष है। इसी परिदृश्य में आज भाजपा सत्ता के सपने के कारण एकदम खेमों में बंटती नजर आ रही है। सभी खेमे यह भ्रम पाले हुए हैं कि उन्हे आसानी से सत्ता हालिस हो जायेगी। भाजपा में केवल प्रेम कुमार धूमल में ही वीरभद्र से टकराने का साहस है वीरभद्र भी इस तथ्य को स्वीकरते हैं इसीलिये वही वीरभद्र के निशाने पर रहते हैं। कांग्रेस में आज भी वीरभद्र के खिलाफ कोई भी खुली बगावत का साहस नही कर पा रहा है जबकि वह केन्द्र की जांच ऐजैन्सीयों से बुरी तरह घिरे हुए है। इस परिदृष्य में यदि भाजपा की परिवर्तन रैली का आकलन किया जाये जो यह नही लगता कि इससे कोई बड़ा दीर्घकालिक लाभ भाजपा को मिल पायेगा। नगर निगम शिमला पर अब तक भाजपा अपना कब्जा नही कर पायी है। पिछली बार महापौर और उप-महापौर के सीधे चुनाव होने के कारण पार्षदों का बहुमत होने के बावजूद भाजपा जीत कर भी हार गयी थी। इस बार फिर पुराने पैट्रन पर चुनाव होने जा रहे हैं। वाम दल भी पूरी ताकत के साथ चुनाव में होंगे। ऐसे में क्या तिकोने मुकाबले में भाजपा निगम पर कब्जा कर पायेगी यह बड़ी चुनौती उसके सामने होगी। प्रधानमन्त्री द्वारा शिमला में परिवर्तन रैली को संबोधित करने के बावजूद भी यदि भाजपा को सफलता नही मिल पाती है तो इसका नुकसान विधानसभा चुनावों में भी उठाना पड़ सकता है।

मुख्यमन्त्री द्वारा 18 पत्र लिखने के बाद मिले हैं 59 एन एच:विक्रमादित्य

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के लाडले व प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दावे का, कि वह कोका कोला जैसी कंपनियों को उनके पेय में फल फुट डालने का फरमान जारी करेंगे, का मजाक उड़ाया है। सीएम के लाडले ने कहा कि कोका कोला, पेप्सी जैसे जितने भी पेय हैं,उनका अपना एक फार्मूला है व उनमें फल फुट नहीं पड़ते हैं। दुनिया भर में ये कंपनियां कहीं भी अपना फार्मूला नहीं बदलती हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का 2017 का ये सबसे बड़ा झूठ है।

अगर उन्हें बागवानों की इतनी ही चिंता होती तो वो प्रदेश के लिए कोल्ड स्टोर मंजूर करते लेकिन उनकी सरकार ने अब तक केवल एक ही कोल्ड स्टोर मंजूर किया है।

पिता सीएम की निगाहबानी में बड़ा नेता बनने की प्रक्रिया से गुजर रहे

डी.पी.आर.की सैद्धांतिक मंजूरी केवल 10 को ही मिली है डी.पी.आर. 200 करोड़ मे से एक भी पैसा नही मिला

युवा कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि ऐतिहासिक रिज पर अब तक जितने भी प्रधानमंत्रियों ने रैली की प्रदेश के लिए कुछ न कुछ दिया लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के लिए कुछ भी नहीं दिया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रिज पर हुई रैली के दौरान बीजेपी नेताओं ने भी प्रदेश के लिए कुछ नहीं मांगा। पूर्व मुख्यमंत्री धूमल तो यहां तक कह गए थे कि मोदी ने पहले ही बहुत ज्यादा दे दिया है। विक्रमादित्य के स्तर का कोई युवा कुछ इस तरह की बात करे तो समझ में आता है लेकिन सीएम वीरभद्र के अलावा धूमल व नड्डा जैसे बड़े नेता भी कुछ न मागे तो ये प्रदेश की जनता के साथ मजाक के सिवा कुछ नहीं है।

बहरहाल, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह को खुद टिकट मिले या न मिले लेकिन उन्होंने दिलचस्प दावा किया कि कांग्रेस पार्टी के ऐसे पांच सात नेता हैं जिनको टिकट नहीं मिलने चाहिए। इस बावत युवा कांग्रेस को फीडबैक मिला है व उन्होंने इस फीडबैक को कांग्रेस के आला नेताओं तक पहुंचा भी दिया है। हालांकि इस बावत कोई सबूत मीडिया के साथ शेयर नहीं किया गया। वो खुद कहां से लड़ेंगे इस सवाल को वो टाल गए। कांग्रेस में एक परिवार से एक ही सदस्य को टिकट देने का दबाव बनता जा रहा है।

कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश प्रभारी व अब मोदी सरकार में मंत्री वीरेंद्र चौधरी को लपेटते हुए उन्होंने एक और बड़ा दावा किया कि भाजपा-कांग्रेस के कई नेताओं व विधायकों को बीजेपी में ले जाने के लिए लुभा रही है। लेकिन बीजेपी इसमें कामयाब नहीं हो पाएगी। कोई मंत्री भी इनमें शामिल हैं, इस बावत उन्होंने कहा कि वो ये नहीं बता सकते। सफाई देते हुए कहा कि वीरेंद्र सिंह इस तरह के दावा करते फिर रहे हैं। याद रहे कि 2012 के विधानसभा चुनावों के दौरान वीरेंद्र चौधरी कांग्रेस पार्टी से हिमाचल के प्रभारी थे। बताते हैं कि वो उस समय भाजपा के साथ भी संपर्क में थे।

इसी बात को लेकर उनकी वीरभद्र सिंह के साथ तनातनी भी चली थी। उनका ये दावा मोदी की तरह ही जुमला है या इसमें कोई सच्चाई भी है, इसकी पुष्टि नहीं हो सकती क्योंकि विक्रमादित्य सिंह ने नाम लेने से इंकार कर दिया।

यही नहीं युकां अध्यक्ष ने यह

शेष पृष्ठ 8पर.....

'कला उत्सव' को वार्षिक समारोह बनाने पर बल:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने राज्य के उभरते कलाकारों, जो व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहते हैं, को प्रोत्साहित करने के लिये 'हिमाचल आर्टिस्ट वेब पोर्टल' की शुरूआत की। वेब पोर्टल कलाकार की कृतियों का पूरा विवरण प्रदान करेगा और इसके अलावा संपर्क सहित कलाकारों की जानकारी भी उपलब्ध करवाएगा।

वेब पोर्टल का शुभारंभ करने के उपरांत इस अवसर पर संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने शिमला में कला उत्सव के आयोजन के लिये कला, भाषा एवं संस्कृति विभाग के प्रयासों की सराहना की और बधाई दी। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों में नवोदित कलाकारों के कौशल का पता चलता हैऔर उनकी रूचि बढ़ती है।

उत्सव में भाग लेने वाले 10 प्रसिद्ध राष्ट्रीय कलाकार भी इस दौरान बच्चों को सुझाव दे रहे थे। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के दृष्य कला विभाग से 20 विद्यार्थियों सहित पिछले कल से विभिन्न आयु वर्ग के लगभग 170 प्रतिभागियों ने चित्रांकन के लिये अपना पंजीकरण करवाया। मुख्यमंत्री ने भी कैनवस पर रंग भरे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदर्शित चित्रकलाएं उच्च स्तर की थीं और इस तरह के आयोजन गर्मियों के दौरान प्रति वर्ष आयोजित किए जाने चाहिए और इन्हें लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए ताकि नवोदित कलाकार पेशेवरों से प्रेरणा ले सकें और उनसे कुछ सीख सकें। उन्होंने कहा कि कलाकारों को ऐसे आयोजनों में हर साल आमंत्रित कर उन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 'मुझे लगता है कि मन के गहन विचारों को उजागर करने के लिये चित्रांकन से बेहतर कोई अन्य मंच नहीं है'।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि घणाहट्टी के समीप जवाहरलाल नेहरू ललित कला महाविद्यालय का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि ललित कला महाविद्यालय न केवल हिमाचल प्रदेश, बल्कि देश का बेहतरीन संस्थान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कला पाठयक्रमों के लिये छात्रवृति योजना शुरू की गई है।

कला, भाषा एवं संस्कृति विभाग की प्रधान सचिव अनुराधा ठाकुर ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि स्नात्तक तथा स्नात्कोत्तर पाठयक्रमों के लिये प्रति माह क्रमश: 3000 रुपये और 5000 रुपये की छात्रवृति प्रदान करने का प्रावधान किया गया है जो वर्ष में एक बार वितरित की जाएगी।

उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के प्रतिभावान छात्रों को प्रोत्साहन प्रदान करना है ताकि ललित कला के क्षेत्र में उनके कौशल में सुधार किया जा सके। उन्होंने कहा कि हिमाचली कलाकारों को बढ़ावा देने के लिये राज्य में कला उत्सव अपनी तरह का पहला उत्सव है, जहां वेब पोर्टल भी बनाया गया है ताकि लोग कलाकारों से ऑन-लाईन संपर्क कर सके तथा उनकी चित्रकारी भी खरीद सके। वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी, राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष हर्ष महाजन, समाज कल्याण की निदेशक मानसी सहाय ठाकुर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT
'NOTICE INVITING TENDER'

1. The Executive Engineer Shimla Division No. III H.P.PWD , Shimla H.P.-3, on behalf of Governor of H.P. invites the online bids on item in electronic tendering system in 2cover system for the undermentioned work from the eligible and approved contractors /Firms registered with HPPWD Department.

Sr. No.	Name of work	Estimated Cost	EMD Limit	Cost of Tender	Time Allowed
1.	M/T of road from Jagher Nallah to Nariga bridge km 0/00 to 1/300) (SH:- P/L G-I, G-II and 20mm premix carpet.)	14,13,995/-	28, 300/-	500/-	30 days
2.	Construction of parking approach path Type -III -VI at Kasumpti (SH:- Providing and fixing Interlocking tiles in compound /approach of type -IV set No. 1to 24)	10, 98,678/-	22,000/-	500/-	60 days

2. **Availability of Bid Document and mode of submission :** The bid document is available online and bid should be submitted in online on mode on website http://hptenders.gov.in.
Bidder would be register in the web-site which is free of cost .For submission of bids , the bidder is required to have Digital signature Certificate (DSC) from one of the authorized Certifying Authorities (CA) "Aspiring bidders ho have not obtained there ID and password for participating in e-tendering in HPPWD may obtain the same from the website:https://hptenders.govt.in. Digital signature is mandatory to participate in the e-tendering Bidders already possessing the digital signature issued from authorized CAs can use the same in this tender.

3. Key Date :-

1. Date of Online Publication : 25.04.2017. up to 18:00HRS.
2. Document Download Start and End Date 25.04.2017. up to 18:00HRS upto 17-05-2017 16:00HRS
3. Bid Submission Start and End Date 25.04.2017. up to 18:00HRS upto 17:05.2017. up to 16:00HRS HRS.
4. Physical Submission of EMD and Cost of Tender Document. 18.05.2017. upto 10:30. HRS.
5. Date of opening of Technical Bid 18.05.2017 11:00 HRS.
6. Date of opening of Financial Bid.

4. TENDER DETAILS
The Tenders documents shall be uploaded online in 2 cover.
i) **Cover -I:-** Shall contain scanned copies of all " Technical Documents/eligible Information"below.
ii) **Cover-2:-** Shall contain. BOQ/Financial Bid where contractor will quote his offer for each item.

5. SUBMISSION OF ORGINIAL DOCUMENTS:-The bidders are required to submit (a) original demand draft towards the cost of bid document and (b) original bid security Earnest Money Deposit (EMD) and other Technical Documents in the O/o Executive Engineer Outer Seraj Division H.PPWD Nirmand as specified in Key dates Sr .No. 3 on Tender Opening Date. Failing which the bid will be declared non-responsive.

6.BID OPENING DETAILS:- The bids shall be opened on 18.05.2017 upto 11:00 HRS in the office of Executive Engineer Shimla H.P. by the authorized officer. In their interest the tenders are advised to be present along with original documents at the time of opening of tenders. If the office happens to be closed on the date of opening of the bids a specified ,the bids will be opened on the next working day at the same time and venue.

7. The bids for the work shall remain valid for acceptance for a period not less than 120 days .after the deadline date for bid submission.

8. Other details can be seen in the biding documents. The officer inviting tender shall not be held liable for any delays due to system failure beyond its control. Even thought the system will attempt to notify the bidders of any bids updates. The Employer shall not be liable for any information not received by the bidder. It is the bidders responsibility to verify the website for the latest information related to the tender.

Adv. No.-0301/17-18 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

मुख्यमंत्री ने इमानदार राज्य का श्रेय दिया प्रदेश के लोगों को

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने हिमाचल प्रदेश को देश में सबसे ईमानदार राज्य आंका जाने के लिये इसका श्रेय राज्य के लोगों को दिया है। उन्होंने कहा कि यह गर्व की बात है कि मीडिया स्टडीज केन्द्र द्वारा हाल ही में किए गए सर्वेक्षण में हिमाचल को देश का सबसे ईमानदार राज्य आंका है। सर्वेक्षण में पता चला है कि राज्य के लोग लोक सेवकों से अपने कार्य करवाते समय उन्हें दूसरे राज्यों के मुकावले काफी इमानदार पाते हैं। उन्होंने कहा कि यह सर्वेक्षण लोगों द्वारा अपने कार्य करवाने के लिये रिश्वत देने के अनुभव के आधार पर 20 राज्यों में किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सर्वेक्षण राज्य के लोगों में इमानदारी व कर्मठता के साथ-साथ नैतिक मूल्यों को भी उजागर करता है। उन्होंने कहा कि राज्य के लोग कर्तव्यपरायण हैं और सच्चाई व इमानदारी पर विश्वास करते हैं।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि वे लोग अधिक भ्रष्ट हैं जो दूसरों पर उंगलियां उठाते हैं और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं।

सर्वेक्षण के दौरान राज्य के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रें के 3000 लोगों को शामिल किया गया और प्रत्येक हिमाचली को गौरव होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश भ्रष्टाचार के मामले में राज्यों की सूची में सबसे नीचे है।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक-जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार-ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

राज्यपाल ने शिमला दौरे पर की प्रधानमंत्री का अगवाई

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने जुब्बड़हट्टी हवाई अड्ढे पर पहुंचने पर देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का भव्य स्वागत किया, जहां से प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय हवाई सम्पर्क 'उड़े देश का आम नागरिक' (उड़ान) योजना की शुरूआत की। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों सहित अनाडेल हवाई अड्ढे पर प्रधानमंत्री को भावभीनी विदाई दी।

राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री ने सीआरपीएफ जवानों पर हमले पर किया शोक व्यक्त

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत तथा मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने छत्तीसगढ़ में नक्सलियों द्वारा सीआरपीएफ जवानों पर किए गए हमले, जिनमें 25 जवान शहीद हो गए थे, पर शोक व्यक्त किया है। इस हमले में शहीद हुए जवानों में हिमाचल के दो जवान शामिल हैं।

अपने शोक संदेश में राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सलियों का यह कृत्य कायरतापूर्ण और निंदनीय है, जिसके लिए लोकतंत्र में कोई भी स्थान नहीं है। उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि और शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। उन्होंने हमले में घायल जवानों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की भी कामना की है।

इस हमले में शहीद हुए जवानों में पालमपुर के संजय कुमार और मंडी के सुरेंद्र ठाकुर शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने की हिमाचल के प्रत्येक सुकमा शहीद को 20 लाख की घोषणा

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने हि.प्र. मुख्यमंत्री सैनिक कल्याण निधि से छतीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों के हमले में सीआरपीएफ 74 बटालियन में शहीद हुए हिमाचल प्रदेश के जिला पालमपुर के चचियां से श्री संजय कुमार तथा जिला मण्डी से नेरचौक के श्री सुरेन्द्र कुमार प्रत्येक के परिजनों को 20-20 लाख रुपये की अनुग्रह राशि स्वीकृत की है।

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT
'NOTICE INVITING TENDER'

1. The Executive Engineer HPPWD Sangrah Distt Sirmour .H.P on behalf of Governor of H.P. invites the online bids on item rate, in electronic tendering system , 2 cover system for the under mentioned work from the eligible and approved contractors/firms registered with HPPWD Department.

Sr. No.	Name of work	Estimated Cost	EMD Limit	Cost of Tender	Time Allowed	Eligible Class of Contractor
1.	R/R damages on Nohradhar Punnerdhar road km 0/00 to 17/00 (SH:- c/o Retaining wall at RD 7/065 to 7/080)	1,68,471/-	3500/-	350/-	Three Months	Class D
2.	R/R damages on Nohradhar Punnerdhar road km 0/00 to 17/00 (SH:- c/o Retaining wall at RD 15/135 to 15/150)	1,10,628/-	2500/-	350/-	Three Months	Class D

2. **Availability of Bid Document and mode of submission :** The bid document is available online and bid should be submitted in online on mode on website http://hptenders.gov.in. Bidder would be register in the web-site which is free of cost .For submission of bids , the bidder is required to have Digital signature Certificate (DSC) from one of the authorized Certifying Authorities(CA) "Aspiring bidders ho have not obtained there ID and password for participating in e-tendering in HPPWD may obtain the same from the website:https://hptenders.govt.in. in /digital signature is mandatory to participate in the e-tendering Bidders already possessing the digital signature issued from authorized CAs can use the same in this tender.

3. .Key Date :-

1. Date of Online Publication : 03.05.2017. at 4:30PM.
2. Document Download Start and End Date 03.05.2017 at 5:00PM upto 24-05-2017 at 5:00PM.
3. Bid Submission Start and End Date 03.05.2017 at 5:00AM upto 24.05.2017. up to 5:00PM.
4. Physical Submission of EMD and Cost of Tender Document. 25.05.2017.upto11:00PM.
5. Date of opening of Technical Bid 18.05.2017 11:00 HRS.

4. TENDER DETAILS
The Tenders documents shall be uploaded online in 2 cover.
i) Cover -I Shall contain scanned copies of all " Technical Documents/eligible Information"below.
ii) Cover-2:- Shall contain. BOQ/Financial Bid where contractor will quote his offer for each item.

5. SUBMISSION OF ORGINIAL DOCUMENTS:-The bidders are required to submit (a) original demand draft towards the cost of bid document and (b) original bid security Earnest Money Deposit (EMD) and other Technical Documents in the O/o Executive Engineer Sangrah Division H.PPWD Sangrah as specified in Key dates Sr .No. 4 on Tender Opening Date. Failing which the bid will be declared non-responsive.

6. BID OPENING DETAILS: The bids shall be opened on 25.05.2017 at 11:30 HRS in the office of Executive Engineer Sangrah Divisdion HPPWD Sangrah H.P. by the authorized officer. In their interest the tenders are advised to be present along with original documents at the time of opening of tenders. If the office happens to be closed on the date of opening of the bids a specified ,the bids will be opened on the next working day at the same time and venue.

7. The bids for the work shall remain valid for acceptance for a period not less than 90/120 days .after the deadline date for bid submission.

8. Other details can be seen in the biding documents. The officer inviting tender shall not be held liable for any delays due to system failure beyond its control .Even thought the system will attempt to notify the bidders of any bids updates. The Employer shall not be liable for any information not received by the bidder. It is the bidders responsibility to verify the website for the latest information related to the tender.
The provision of notification issued vide Additional chief Secretary (PW) to the Govt. of H.P. Shimla notification No. PBW (B) 22-1/2002 dated 26.05.2015 shall also be application.

Adv. No.-0359/17-18 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

मुख्यमंत्री ने किया प्रधानमंत्री का स्वागत

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने जुब्बड़हट्टी हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, जहां से प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय हवाई सम्पर्क 'उड़े देश का आम नागरिक' (उड़ान) योजना की शुरूआत की।

प्रधानमंत्री ने शिमला से नई दिल्ली के लिए उड़ान योजना के अन्तर्गत प्रथम उड़ान के उद्घाटन के लिए 'एलायन्स एयर' के संचालन दल को हरी झंडी सौंपी। इसके अतिरिक्त, उन्होंने ऑनलाईन विडियो सम्पर्क के माध्यम से आन्ध्रप्रदेश के कडप्पा हवाई अड्डे तथा महाराष्ट्र के मारथवाड़ा क्षेत्र में नादेड़ हवाई अड्डे से अन्य उड़ानों के उद्घाटन भी किए।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि अनुरक्षित रूटों पर उड़ान सम्पर्क निश्चित रूप से सन्तुलित क्षेत्रीय उन्नति को प्रोत्साहित करेगा और आम आदमी के लिए सस्ती उड़ान सुविधा मिलेगी तथा समय की भी बचत होगी।

वीरभद्र सिंह बिलासपुर में 146 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित होने वाले हाइड्रो इंजीनियरिंग कालेज की आधारशिला के दौरान भी प्रधानमंत्री के साथ थे। इस में से 76 करोड़ रुपये की राशि का योगदान राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (एनएचपीसी) तथा राष्ट्रीय थर्मल उर्जा निगम (एनटीपीसी) द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार इसी वित्तीय वर्ष से कालेज में कक्षाएं आरम्भ करने की संभावनाओं का पता लगाएगी। आरम्भ में सिविल तथा इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के दो पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे।

राज्य सरकार ने बिलासपुर जिला के बन्दला में इस कालेज के निर्माण के लिए भूमि प्रदान की है।

इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को हिमाचली टोपी से सम्मानित किया और उन्हें कांगड़ा का एक लघु चित्र भी भेंट किया।

इसके पश्चात,वीरभद्र सिंह परिवहन, नागरिक उड्यन और तकनीकी शिक्षा मंत्री जी.एस.बाली, महापौर संजय चौहान तथा राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नरेन्द्र मोदी को अनाडेल हवाई अड्डे पर गर्मजोशी के साथ विदाई दी।

मुख्यमंत्री ने किया दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल के नए परिसर का लोकार्पण

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने 35 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल (रिपन) का नया परिसर लोगों को समर्पित किया। सात मंजिला केन्द्रित गर्म (सेंट्रली हिटड) इस इमारत में पार्किंग, दवाईयों की दुकानें, ब्लड बैंक जैसी बुनियादी सुविधाओं के अलावा आर्थो वार्डस, एमआरआई, सिटी स्कैन इत्यादि सुविधाएं होंगी। नए परिसर में 135 बिस्तरों सहित अस्पताल में अब बिस्तरों की कुल क्षमता बढ़कर 300 हो गई है। इसके अतिरिक्त, अस्पताल आने वाले रोगियों के लिए दो मंजिला पार्किंग की सुविधा काफी मदद्गार होगी।

मुख्यमंत्री ने कसुम्पटी के परिमहल में 14.11 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय भवन की आधारशिला भी रखी। छः मंजिला इस भवन में पार्किंग, जलपान गृह, सभागार इत्यादि सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।

मुख्यमंत्री ने की हरोली उत्सव के उद्घाटन पर भव्य शोभायात्रा की अगुवाई

शिमला/शैल। जिला ऊना का तीन दिवसीय हरोली उत्सव भव्य पंजाबी संस्कृति के लोक नृत्य गिद्दे के साथ आरम्भ हुआ । मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे।

हरोली विधानसभा के बढेरा मैदान में हरोली क्षेत्र की 5000 से अधिक ग्रामीण महिलाओं ने एकत्रित होकर सामूहिक गिद्दे की प्रस्तुति दी।

मुख्यमंत्री ने इस भव्य मेगा लोक नृत्य कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज कराते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश अपनी विविध संस्कृति तथा रीति-रिवाजों के लिए जाना जाता है तथा हर क्षेत्र की अपनी संस्कृति होती है जो हिमाचली होने के साथ-साथ उस क्षेत्र के लोगों की पहचान भी दर्शाती है।

यह प्रथम अवसर है जब'स्वां वुमैन फैडरेशन' द्वारा आयोजित भव्य पंजाबी लोकनृत्य में सामूहिक रूप से इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपने जिले की संस्कृति को प्रोत्साहित करने तथा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भाग लिया। इस फैडरेशन में 9000 से अधिक सदस्य महिलाएं स्वंय सहायता ग्रुपों के रूप में जुड़ी हैं।

उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण तथा इस क्षेत्र की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस मेगा गिद्दा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्कूली की वरिष्ठ छात्राओं ने भी गर्मजोशी के साथ इस गिद्दा कार्यक्रम में भाग लिया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री का हरोली पहुँचने पर भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने खुली जीप में बढेरा से कांगड़ा तक शोभायात्रा की अगुवाई की तथा मेले में विभिन्न सरकारी विभागों तथा गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्रदेश तथा हरोली विधानसभा क्षेत्र में हुए विकास को दर्शाती प्रदर्शनियों का उद्घाटन भी किया।

स्वतंत्रता सेनानियों की शिकायतों का निवारण एक माह में करने के निर्देश:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने स्वतंत्रता सेनानी कल्याण बोर्ड की 18वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों की सभी समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर एक माह के भीतर किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार स्वतंत्रता सेनानियों के घरों को सम्पर्क सड़कों से जोड़ रही है। उन्होंने इस सुविधा से वंचित स्वतंत्रता सेनानियों की सूची तैयार करने के निर्देश जारी किए।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की 'सम्मान राशि' को बढ़ाकर 15 हजार रुपये किया है और इतनी ही बढ़ौतरी स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं तथा अविवाहित बेटियों की पेंशन में कर इसे 5 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये किया गया है और शीघ्र ही इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके अतिरिक्त, स्वतंत्रता सेनानियों के अंतिम संस्कार के लिए सम्मान राशि को मौजूदा 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये किया गया है। इसी प्रकार स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं की अन्त्येष्टि के लिए आर्थिक सहायता को 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 20 हजार रुपये किया गया है।

उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों की पौत्रियों की विवाह अनुदान राशि को 21 हजार रुपये से बढ़ाकर 31 हजार रुपये किया गया है।

मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों की विवाहित लड़कियों तथा पौत्रियों को सरकारी नौकरियों में मौजूदा 2 प्रतिशत आरक्षण के दायरे में लाने का आश्वासन दिया, जिसके लिए उन्होंने मामले में तहकीकात के आदेश दिए।

बैठक में सूचित किया गया कि कांगड़ा जिला के दाड़ी में सुकेत सत्याग्रह स्मारक की स्थापना के लिए भूमि लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित कर दी गई है।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि विल्ली पार्क के समीप निर्माणाधीन परिधि गृह में पांच कमरे स्वतंत्रता सेनानियों तथा उनके आश्रितों के लिये आरक्षित रखें जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों में स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के बैकलॉग को यथाशीघ्र भरा जाएगा।

इससे पूर्व, मुख्य सचिव वी.सी. फारका ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और स्वतंत्रता सेनानियों तथा उनके आश्रितों के कल्याण के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी।

स्वतंत्रता सेनानी दुनी चन्द, हरी सिंह चौहान तथा किरपा राम, विधायक संजय रत्न, अतिरिक्त मुख्य सचिव तरूण श्रीधर, डा. श्रीकांत बाल्दी अन्य अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।

हिमाचल प्रदेश में विश्व बैंक की 665 करोड़ रू. की 'वनों से समृद्धि' परियोजना जल्द शुरू:भरमौरी

शिमला/शैल। ठाकुर सिंह भरमौरी, वन एवं मत्स्य मंत्री हिमाचल प्रदेश ने जानकारी दी कि हिमाचल प्रदेश में जल्द ही विश्व बैंक एवं प्रदेश सरकार के सहयोग से 665 करोड़ रू. की परियोजना आरम्भ की जाएगी। इस परियोजना को 80:20 के अनुपात में विश्व बैंक व प्रदेश सरकार कार्यन्वित करेगें। यह परियोजना प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर पांच वर्षो की अवधि के लिए लागू की जाएगी, जिसमें वनों की समृद्धि हेतु व्यय किया जाएगा।

भरमौरी ने बताया कि इस परियोजना का मुख्यालय हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में होगा। उनके अनुसार परियोजना की प्रारम्भ की तैयारी प्रदेश सरकार ने कर दी है तथा भारतीय वन सेवा के अधिकारी समीर रस्तोगी को मुख्य परियोजना अधिकारी नियुक्त कर दिया है।

उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि इस परियोजना द्वारा प्रदेश के ग्रामीण ईलाकों के लोगों की आय में वृद्धि होगी, क्योकि परियोजना द्वारा गैर काष्ठ वन उपज(Non Timber Forest Produce) के उत्पादन व संग्रह पर बल दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस परियोजना द्वारा वनों से पारम्परिक ढ़ग से आय प्राप्त करने के साथ-2 अन्य विकल्पों पर भी ध्यान दिया जाएगा, जैसे ईको-टूरिज्म की गतिविधियों पर बल दिया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस परियोजना द्वारा वनों में समृद्धि हेतु कार्य किए जाने से हमारे जलविद्युतीय परियोजनाओं की अवधि में वृद्धि होगी, क्योंकि इससे भू-कटाव पर रोक लगेगी एवं नदियों द्वारा बांधों में गाद की मात्रा कम होगी तथा साथ ही जल की गुणवता में भी वृद्धि होगी जिससे पीने के लिए ही नहीं अपितु सिंचाई हेतु भी अच्छे जल की प्राप्ति होगी। उनके अनुसार इस परियोजना द्वारा दीर्घ कालिन परिणाम जैसे वन आवरण में वृद्धि भी देखने को मिलेगी।

भरमौरी ने जानकारी देते हुए कहा कि परियोजना के संदर्भ में विश्व बैंक की नौ सदस्यों की टीम इन दिनों शिमला में परियोजना के विभिन्न पहलुओं की जानकारी हेतु आई हुई है। विश्व बैंक की टीम की अध्यक्षता मार्सेलो अर्सेवी, वरिष्ठ पर्यावरणविद् कर रहे हैं तथा वे वन विभाग के अधिकारियों के ईलावा अन्य विभाग जैसे पर्यटन, उद्योग, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, ऊर्जा के विभागाध्यक्षों व उच्च अधिकारियों के साथ मिल रहे हैं, जिससे परियोजना के सफल कार्यन्वयन हेतु योजना बनाई जा सके।

वन विभाग परियोजनाओं में कार्यरत दैनिक भोगी कर्मचारियों के लिए नई नीति

शिमला/शैल। वन एवं मत्स्य मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने जानकारी देते हुए कहा कि वन विभाग हिमाचल प्रदेश में चल रही बाह्य सहायता की मध्य हिमालय जलागम विकास परियोजना, स्वां नदी परियोजना, कण्डी परियोजनाऔर इण्डो-जर्मन चंगर परियोजना में कार्यरत कई दैनिक भोगी व अनुबन्ध पर नियुक्त किए गए कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक नई नीति बनाई है।

वन मन्त्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश वन विभाग में 1990 से 2017 तक चल रही इन विभिन्न परियोजनाओं में कई दैनिक भोगी व अनुबन्ध पर कर्मचारी व अधिकारी नियुक्त किए गए थे और लगभग 25 वर्ष तक इन लोगों ने सत्य कर्तव्य निष्ठा से प्रदेश के दुर्गम व दूर दराज के जन जातीय क्षेत्रों में वनों की समृद्धि व सुरक्षा के लिए अपनी सेवाएं इन परियोजनाओं में दी है। वन विभाग की नीतियों व कार्यो को इन लोगों ने घर-घर तक पहुंचाया है। उनकी कार्य कुशलता व भविष्य को मध्यनज़र रखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने इनके लिए नई नीति की घोषणा की है। इस नीति के तहत इन सभी कर्मचारियों को निरन्तर कार्य प्रदान करने के लिए हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन समीति (Himachal Pradesh Natural Resource Management Society) के अन्तर्गत पंजिकृत करके उचित वेतन पर नियुक्त किया जाएगा। प्रदेश में वन विभाग या अन्य विभाग में किसी परियोजना के आरम्भ होने पर इन कर्मचारियों व अधिकारियों को सर्वप्रथम कार्य के लिए सुअवसर प्रदान किया जाएगा।

ठाकुर सिंह भरमौरी ने बताया कि वन विभाग के सभी उच्च वन अधिकारियों व वृतों के अरण्यपालों, वन मण्डल अधिकारियों व कर्मचारियों को यह आदेश दे दिए गए हैं कि वह वनों की आग से सुरक्षा के लिए तत्पर रहें और वन विभाग के कर्मचारियों व स्थानीय जनता के साथ मिलकर बैठकें करें व लोगों को जागृत करके उनके सहयोग से वन अग्नि की घटनाओं को होने से रोकें। वैसे तो इस वर्ष अभी तक इन्द्र देवता की कृपा से वन अग्नि की घटनाएं कम हुई हैं फिर भी वन अग्नि की सूचना फिल्ड स्टाफ से रोज़ लेते रहें। फायर सिज़न के दौरान इन फायर वाचर तैनात किया जाए व वनों को आग से बचाने के लिए तत्परता से अपना कार्य करें।

अपमानित हो के जीने से अच्छा मरना है, मृत्यु तो बस एक क्षण का दुःख देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुःख लाता है। .....चाणक्य

सम्पादकीय

मोदी भी कर गये भ्रष्टाचार पर राजनीति

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शिमला में भाजपा द्वारा आयोजित परिवर्तन रैली को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुख्यमन्त्री का नाम लिये बगैर कहा कि जिन्होने इतने समय तक प्रदेश का शासन चलाया है आज उनका अधिकांश समय वकीलों से सलाह लेने में ही गुजर रहा है। मोदी के सहयोगी मन्त्री नड्डा ने भी नाम लिये बगैर ही वीरभद्र पर निशाना साधा। वीरभद्र अपने खिलाफ चल रही जांच के लिये वित्त मन्त्री अरूण जेटली का नाम लेकर उन पर षडयंत्र का आरोप लगा चुके हैं। उनका आरोप है कि केन्द्र सरकार जांच एजैन्सीयों का अपने विरोधियों के खिलाफ दुरूपयोग कर रही है। केन्द्र में जब कांग्रेस नीत यूपीए सरकार थी तब सीबीआई को देश के सुप्रीम कोर्ट ने पिंजरे का तोता कहा था। आज भाजपा नीत एनडीए सरकार है और जांच ऐजैन्सीयां वही हैं। आज भी दुरूपयोग का आरोप लग रहा है। अन्तर केवल इनता भर है कि आरोप लगाने वाले बदल गये हैं। हर सरकार यह दोहराती है कि भ्रष्टाचार कतई बर्दाशत नही किया जायेगा। मोदी सरकार भी यह परम्परा निभा रही है।

मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ वर्ष 2013 से वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण की याचिका के परिणाम स्वरूप जांच चल रही है जो अभी तक पूरी नही हुई है। इस जांच को पूरा होने में कितना समय लगेगा यह कहना संभव नही है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि जब तक यह जांच पूरी नही हो जाती हैं इसका पूरा-पूरा राजनीतिक लाभ उठाया जायेगा। लेकिन क्या प्रधानमन्त्री के स्तर पर भी ऐसा किया जाना चाहिए? क्योंकि इस मामले में जांच ऐजैन्सीयां केन्द्र सरकार की हैं उनके ऊपर सरकार का प्रशासनिक नियन्त्रण है। ऐसे में किसी भी मामले में जांच को प्रभावित किये बिना क्या उसकी जांच एक तय समय सीमा के भीतर नही हो जानी चाहिए? क्या एक जांच को सालों तक चलाये रखा जाना चाहिये? जब ऐसा होता है तब उसके साथ राजनीति जुड़ जाती है। सत्ता संभालते ही प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ने यह ऐलान किया था कि '' न खाऊंगा और न ही खाने दूंगा'' लेकिन पिछले दिनों अरूणांचल के पूर्व मुख्यमन्त्री स्व. काली खो पुल्ल का जो पत्र मरणोपरान्त सार्वजनिक हुआ है क्या उसमें लिखे गये तथ्यों पर जांच नही होनी चाहिए थी और इसका जिम्मा मोदी सरकार पर नहीं आता है। इस पत्र के बाद मोदी के अपने सहयोगी केन्द्रिय स्वास्थ्य मन्त्री जे.पी. नड्डा को लेकर रामबहादुर राय के यथातवत में कई गंभीर आरोप लग चुके है। एम्ज़ की जमीन के मामलें में हजारों करोड़ के घपले के आरोप लग चुके हैं। रामबहादुर राय संघ में भी एक बड़ा नाम है। परन्तु नड्डा पर लगे आरोपों को लेकर न तो मोदी की सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया आयी है और न ही स्वयं नड्डा ने इसका कोई खण्डन किया है या ''यथावत'' को मानहानि का नोटिस ही दिया है।

इसलिये जब प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जैसा व्यक्ति वीरभद्र पर नाम लिये बगैर हमला करता है तो स्वाभाविक रूप से उसमें राजनीति की ही गंध आयेगी। प्रधानमन्त्री के स्तर से तो परिणाम आने चाहिए और खास तौर पर तब जब स्वयं केन्द्र की जांच ऐजैन्सीयों की कार्यशैली का मामला हो। क्योंकि इस मामलों में ईडी की जो कार्यशैली अब तक सामने आ रही है उससे ऐजैन्सी की निष्पक्षता पर ही सवाल उठने शुरू हो गये हैं। जांच ऐजैन्सी के स्तर पर संबद्ध मामले की जांच को एक निश्चित समय सीमा के भीतर जांच पूरी करके चालान अदालत तक पहुंचाना होता है। परन्तु इस मामले में जांच को जिस तरह से लम्बा किया जा रहा है उससे यह संकेत उभरने शुरू हो गये हैं कि इस मामले में जांच परिणाम से ज्यादा राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास हो रहा है। वैसे भी भ्रष्टाचार को लेकर प्रदेश में भाजपा का आचरण कुछ अलग ही रहा है। भाजपा ने बतौर विपक्ष 2003 से 2007 के कार्यकाल में जो आरोप पत्र कांग्रेस सरकार के खिलाफ सौंपे थे उन पर सत्ता में आने के बाद कोई कारवाई नही हुई है। उन आरोप पत्रों पर भी कवेल राजनीति ही हुई थी जो अब वीरभद्र के मामले में हो रही है।

हाईड्रो इंजीनियरिंग कालेज से लाभान्वित होगा जल विद्युत क्षेत्र

हिमाचल प्रदेश एक छोटा पर्वतीय राज्य है। प्रकृति ने इस पहाड़ी राज्य के लोगों को अनेक प्राकृतिक उपहारों से नवाजा है। प्रकृति के ये खजाने जहां पर्यटन क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में विद्यमान हैं वहीं यहां वर्ष भर बहने वाली अनेक नदियों में विद्युत उत्पादन की अपार क्षमता मौजूद है। हिमाचल प्रदेश ऊर्जा सरप्लस राज्य है जहां मांग पर ऊर्जा उपलब्ध होने के साथ-साथ आम उपभोक्ताओं को नियमित आपूर्ति के अतिरिक्त उद्योगों, वाणिज्य व व्यवसायों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं।

हिमाचल प्रदेश में 24 हजार मैगावाट जल विद्युत के दोहन की क्षमता है जिसे राज्य में बहने वाली नदियों से तैयार किया जा सकता है। इसमें से राज्य ने विभिन्न पूरी हो चुकी तथा निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए 21500 मैगावाट का आबंटन किया है। इस क्षेत्र में मौजूद क्षमता का अधिक से अधिक दोहन करने के लिए इसमें सार्वजनिक तथा निजी उद्यमियों को शामिल किया गया है। विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से अभी तक 10351 मैगावाट की क्षमता का पहले ही सफलतापूर्वक दोहन व संचालन किया जा रहा है। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड तथा नेशनल थर्मल विद्युत निगम जैसे बड़े राष्ट्रीय ऊर्जा उत्पादक उपक्रम राज्य में जल विद्युत उत्पादन में सक्रिय भूमिका निभाकर राज्य की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में अहम योगदान दे रहे हैं।

1281.50 करोड़ लागत की 100 मैगावाट की ऊहल चरण-3 परियोजना का निर्माण पूरा होने वाला है। राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को 16 मैगावाट की देवीकोठी, 16.50 मैगावाट की साईकोठी, 18 मैगावाट की हेल जल विद्युत परियोजना, 18 मैगावाट की रायसन, 60 मैगावाट की बटसेरी तथा 9 मैगावाट की नई नोगली परियोजनाएं आबंटित की हैं।

विश्व के वर्तमान पर्यावरण परिदृश्य के मद्देनजर उद्योग एवं वाणिज्य के परिसंचालन के लिए स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा पर बल दिया जा रहा है। राज्य सरकार भी पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है तथा परियोजना वाले क्षेत्रों में विकास को विशेष तरजीह प्रदान की जा रही है।

इन परियोजनाओं में विभिन्न स्तरों पर विभिन्न श्रेणियों के कुशल कामगारों की बड़ी संख्या में आवश्यकता होगी। वर्तमान में भी प्रदेश में कुशल इंजीनियरों की कमी होने के कारण बाहरी राज्यों के इंजीनियरों की सेवाएं लेनी पड़ रही है।

बिलासपुर जिला के बंदला में हाईड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज के खुलने से जल विद्युत के क्षेत्र में विशेषज्ञता वाले इंजीनियर तैयार होंगे जिससे उद्योगों, विशेषकर जल विद्युत परियोजनाओं में इंजीनियरों की मांग को पूरा किया जा सकेगा।

राज्य सरकार ने इस हाईड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के सार्वजनिक उद्यमियों एनटीपीसी तथा एनएचपीसी का सहयोग प्राप्त करने की पहल की है। इस कालेज में मैकेनिकल, सिविल, इलैक्ट्रिकल तथा कम्प्युटर साइंस आदि चार संकाय होंगे जिसके आरम्भ होने से प्रदेश के युवाओं को उनके घर-द्वार पर हाईड्रो इंजीनियरिंग की शिक्षा सुलभ होने के साथ-साथ रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे।

हाईड्रो इंजीनियरिंग कालेज के लिए पर्याप्त भूमि प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने तकनीकी शिक्षा विभाग को 62 बीघा जमीन हस्तांतरित की है। सरकार ने इस संस्थान के परिसर के निर्माण के लिए 82 करोड़ रूपये की प्रशासनिक मंजूरी भी प्रदान की है।

गाड़ियों पर लाल बत्ती लगाने की परंपरा का अंत

वीआईपी संस्कृति के लिए बड़ा झटका

‘ निवेदिता खांडेकरे’

ग्रीस के प्रसिद्ध दार्शनिक ने कहा था कि ‘अच्छी शुरुआत आधी सफलता होती है’। सरकारी गाड़ियों पर लाल बत्ती लगाने की संस्कृति को खत्म करने के लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया निर्णय इस दिशा में लड़े जा रहे युद्ध के खिलाफ एक अच्छी शुरुआत है।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार 19 अप्रैल 2017 को राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री सहित विभिन्न वीआईपी गणमान्य व्यक्तियों के वाहनों पर लाल एवं अन्य रंगों की बत्तियां लगाने की परंपरा को खत्म करने के लिए मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल की बैठक में इस निर्णय को लिए जाने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि ‘प्रत्येक भारतीय नागरिक खास है, प्रत्येक भारतीय नागरिक वीआईपी है।’

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने देशभर में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत वाहनों के ऊपर लगी लाल बत्ती को हटाने का निर्णय लिया। सरकार का मानना है कि वाहनों के ऊपर लगी लाल बत्ती से वीआईपी संस्कृति का प्रदर्शन होता है, और एक लोकतांत्रिक देश में इस तरह की किसी भी संस्कृति के लिए स्थान नहीं है। वाहनों के ऊपर लगी इन लाल बत्तियों की कोई प्रासंगिकता नहीं है। हालांकि एंबुलेंस, दमकल आदि आपातकालीन और राहत कार्यों के अंतर्गत सेवा कार्यों में लगे वाहनों पर इस तरह की बत्तियों को इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाएगी। इस निर्णय के मद्देनजर, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नियमों में आवश्यक संशोधन करेगा। यह बात केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय के बाद सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी संक्षिप्त ब्यान में कही गई।

तत्काल, अगले ही दिन गुरुवार 20 अप्रैल 2017 को इस संबंध में राजपत्रित अधिसूचना (गैजेट नोटिफिकेशन) जारी कर दी गई।

इसके तुरंत बाद यह टेलीविजन समाचार चैनलों और समाचार पोर्टल्स पर बड़ी खबर के रूप में दिखने लगी। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर इस खबर के संबंध में खुशनुमा संदेशों की झड़ी लग गई। वाहनों से लाल, नीली, ऑरेंज (नारंगी) आदि बत्तियों को हटाने की खबर जैसे ही देशभर में फैली, तो जिन लोगों को इस तरह की बत्तियों का उपयोग करने की अनुमति थी, उनमें से कई वीआईपी ने तुरंत प्रभाव से अपने वाहनों से बत्ती उतारते हुए फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया आदि पर अपलोड कर दी और हजारों लोगों तक यह संदेश पहुंचाया कि वे कोई विशेष व्यक्ति नहीं, बल्कि समाज का ही एक हिस्सा हैं और समाज के अन्य लोगों की तरह ही आम नागरिक हैं। वाहनों से बत्तियों को हटाकर वीआईपी संस्कृति को खत्म करने के लिए मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय के संदेश को आश्वासन के रूप में देखा जा सकता है, एक वादे के रूप में देखा जा सकता है, देश में बदलाव लाने वाले एक संदेश के रूप में देखा जा सकता है और इस संदेश को देशभर में भेदभाव खत्म करने के रूप में भी देखा जा सकता है।

सर्वोच्च अदालत का फैसला

सरकार ने दिसंबर 2013 के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को आगे बढ़ाते हुए वाहनों पर लगने वाली लाल एवं अन्य रंगों की बत्तियों को हटाने के बारे में यह निर्णय लिया। इस फैसले में कानूनों में संशोधन कर, वाहनों पर लगने वाली लाल बत्ती के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई थी। वीआईपी संस्कृति के बारे में सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि ‘यदि सत्ता कुछ व्यक्तियों तक केन्द्रित रहती है, तो सत्ता को हासिल करने का लालच लोकतंत्र के मूल्यों को खत्म कर देगा। हमने पिछले चार दशकों में जो किया है वह निश्चित रूप से हमारी स्थापित राजनीतिक प्रणाली को झटका पहुंचाएगा। इसके सबसे बेहतर उदाहरण, छोटे से लेकर बड़े सार्वजनिक प्रतिनिधियों और विभिन्न कैडरों के नौकरशाहों सहित विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा वाहनों पर लाल बत्ती आदि का उपयोग किया जाना है। लाल बत्ती सत्ता को प्रदर्शित करती है और जिनके पास इस तरह की बत्तियों को उपयोग करने की सुविधा है और जिनकी पास ऐसी सुविधा नहीं है, उनके बीच बड़े अंतर को दर्शाती है।

इस मामले में न्यायालय द्वारा गठित एमिकस क्यूरी ने अदालत को बताया था कि लाल बत्ती लोगों के लिए एक प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया था, जो लोग इस तरह की बत्ती का उपयोग करते हैं वे खुद को सामान्य लोगों से अलग एवं बेहतर श्रेणी में समझते हैं। उन्होंने न्यायालय को यह भी बताया कि, सरकारी वाहनों पर लाल बत्ती का व्यापक उपयोग उन लोगों की मानसिकता को प्रतिबिम्बित करता है, जिन्होंने भारत में ब्रिटिश सरकार की सेवा की थी, और देश के आम लोगों को गुलाम डराने - धमकाने का प्रयास करते थे।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल की घोषणा के तुरंत बाद, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने वाहनों से लाल बत्ती हटाने की घोषणा कर दी। अपने वाहनों से लाल बत्ती हटाने की घोषणा करने वाले मुख्यमंत्रियों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और कई अन्य राज्य शामिल हैं। कई अन्य राज्यों ने भी जल्द ही इस नियम का पालन किया। यह वीआईपी संस्कृति और लाल बत्ती परंपरा से मुक्ति का एक प्रयास था। दिल्ली और त्रिपुरा सहित कई अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री पहले से ही अपने वाहनों पर लाल बत्ती का उपयोग नहीं कर रहे हैं। हाल ही में, पंजाब और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों (कैप्टन अमरिंदर सिंह और योगी आदित्यनाथ) ने शपथ लेने के तुरंत बाद यह ऐलान किया कि वे लाल बत्ती वाले वाहन का उपयोग नहीं करेंगे। समाचार पत्रों की रिपोर्टों के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने अपने वाहनों से लाल बत्ती हटाने संबंधी आदेश पारित कर दिए हैं।

‘प्रत्येक भारतीय विशेष है, प्रत्येक भारतीय वीआईपी है’

केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वाहनों पर लगने वाली लाल बत्ती को हटाकर इस बत्ती संस्कृति को खत्म करना वास्तव में सही दिशा में उठाया गया एक स्वागत योग्य कदम है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि ‘प्रत्येक भारतीय नागरिक खास है, और प्रत्येक भारतीय नागरिक वीआईपी है’।

मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए इस निर्णय के बाद, लोग उम्मीद कर सकते हैं कि वीआईपी टैग के जरिए मिलने वाला विशेषाधिकार आदि का अंत होगा, और देश का प्रत्येक नागरिक एक समान अवसरों का लुत्फ उठा पाएगा। लोग उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में किसी भी गरीब को वीआईपी कोटे की वजह से बेहतर शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। लोग उम्मीद कर सकते हैं कि दूर - दराज के इलाकों से आने वाला मरीज भी दिल आदि से संबंधित गंभीर बीमारियों का इलाज कराने में सक्षम हो पाएगा। वीआईपी लोगों को प्राथमिकता दिए जाने की वजह से दूर - दराज के इलाके से आने वाले मरीज को किसी दूसरे अस्पताल में नहीं भेजा जाएगा। हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि खुद प्रधानमंत्री ने यह वादा किया है कि,‘प्रत्येक भारतीय खास है, प्रत्येक भारतीय वीआईपी है’। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम लाल बत्ती के रूप में ताकत के प्रतीक बन गई इस संस्कृति का अंत करेगा।

-पसूका-

हिमाचल में 21392 गांवों का राजस्व रिकार्ड ऑनलाइन

हिमाचल प्रदेश में डिजिटल इण्डिया भूमि रिकार्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम का सफल क्रियान्वयन किया गया है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य भूअभिलेखों का अद्यतन, स्वचालित और स्वतः उत्परिवर्तन इंतकाल, शाब्दिक तथा स्थानिक दस्तावेजों का एकीकरण, राजस्व तथा पंजीकरण के बीच अंतर मिलान से जहां राज्य के आम लोगों को भूमि दस्तावेज प्राप्त करने अथवा इनका अवलोकन करने की एक बड़ी सुविधा प्राप्त हुई है, वहीं उनका बहुमूल्य समय व पैसा दोनों की बचत भी हुई है।

प्रथम चरण में 2008 - 09 में डिजिटाइजेशन कार्यक्रम के तहत मण्डी, हमीरपुर तथा सिरमौर जिलों का प्रायोगिक आधार पर चयन किया गया था तथा परियोजना के तहत इन जिलों के लिए 1319.57 लाख रुपये (718. 33 लाख रुपये का केन्द्रीय हिस्सा तथा 601.24 लाख रुपये राज्यांश) स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से 1161. 23 लाख रुपये व्यय किए जा चुके हैं और अभिलेखों के आधुनिकीकरण का कार्य जारी है। वर्ष 2011 - 12 के दौरान इस परियोजना के तहत कांगड़ा, किन्नौर, शिमला तथा ऊना जिलों को चुना गया। इन जिलों के लिये कुल 2972 लाख रुपये स्वीकृत किए गए, जिसमें केन्द्र की ओर से 2231. 77 लाख रुपये तथा राज्य की ओर से 474.27 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं, और अभी तक 522.03 लाख रुपये व्यय किए जा चुके हैं।

वर्ष 2014 - 15 के दौरान शेष जिलों बिलासपुर, चम्बा, कुल्लू, लाहौल - स्पिति तथा सोलन को परियोजना के तहत लाया गया, जिसके लिए 19.904 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। इसमें जिसमें 11.942 करोड़ रुपये का 60 प्रतिशत केन्द्रीय हिस्सा जबकि 709.45 लाख रुपये की राशि राज्य की ओर से जारी की गई।

बंदोबस्त के अन्तर्गत आने वाले गांवों को छोड़कर प्रदेश के सभी 21392 राजस्व गांवों में पूर्ण रूप से रिकॉर्ड ऑफ राइट का डाटा एंट्री कार्य पूरा कर लिया गया है। यह डाटा आम जनमानस के लिए ऑनलाइन उपलब्ध है। राज्य सरकार ने आम लोगों को डिजिटल हस्ताक्षर युक्त आरओरआर की प्रति प्रदान करने के लिए लोक मित्र केन्द्रों को अधिकृत किया है तथा सरकार की ओर से लोकमित्रों द्वारा जारी किए जाने वाले भूमि दस्तावेजों को वैद्यता की मंजूरी प्रदान की गई है। वेब आधारित सरवर पर आरओरआर डाटा के उपलब्ध होने से कोई भी व्यक्ति किसी भी समय इसकी जानकारी प्राप्त कर सकता है।

सभी जिलों में भूकर मानचित्रों का डिजिटाइजेशन आरम्भ कर दिया गया है तथा 12 जिलों में भूकर मानचित्रों के डिजिटलीकरण के लिए तीन सेवा प्रदाता चयनित किए गए हैं। वर्तमान में राज्य में 192049 मुसावियों में से 174295 मुसावियों का डिजिटाइजेशन पूरा कर लिया गया है।

चम्बा, हमीरपुर तथा मण्डी जिलों के डिजिटल भूकर मानचित्र आरओआर के साथ जोड़ दिए गए हैं तथा आम जन की सुविधा के लिए राजस्व विभाग की वैबसाईट पर उपलब्ध हैं। समूचे प्रदेश में जिला, तहसील तथा उपमण्डल स्तरीय कम्प्यूटर डाटा केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

राज्य डाटा केन्द्र की स्थापना शिमला में प्रौद्योगिकी विभाग के राज्य मुख्यालय में की गई है तथा राज्य डाटा केन्द्रों में सरवर पर आरओआर का कम्प्यूटराइज डाटा उपलब्ध है तथा हर समय लोगों की सुविधा के लिए आरओआर का डाटा तहसील आधारित क्लाइंट सरवर से राज्य डाटा केन्द्र के वेब आधारित सरवर पर स्थानांतरित किया गया है। राजस्व अधिकारियों तथा उपपंजीयकों के कार्यालय भी आपस में जुड़े हैं।

सभी तहसीलों में पंजीकरण प्रणाली का कम्प्यूटीकरण कार्य भी पूर्ण कर लिया गया है तथा समूचे प्रदेश में पंजीकरण का कार्य आरओआर के साथ जोड़ा गया है। संबंधित जिलाधीशों द्वारा राजस्व विभाग की वेबसाइट पर निर्धारित की गई सर्कल रेटों के अनुसार भूमि की कीमत की जानकारी भी उपलब्ध करवाई गई है। इसी तरह कम्प्यूटरों के माध्यम से विरासत भार की डाटा एंट्री भी बनाई जा रही है। पुराने दस्तावेजों की स्कैनिंग तथा संरक्षण का कार्य जारी है। सभी जिलों में रिकार्ड कक्षों के आधुनिकीकरण का कार्य भी प्रगति पर है।

खेलों से अनुशासन और टीम भावना विकसीत होती है:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के सुन्नी में 'शिमला ग्रामीण क्रिकेट कप' प्रतियोगिता के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा कि खेलें युवाओं में अनुशासन तथा भाईचारे की भावना उत्पन्न करती हैं और जीवन के लिये नितान्त आवश्यक हैं। मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी व पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित थी। उन्होने कहा कि हमें खेलों से प्राप्त होने वाली क्षमता व मूल्यवान सबक नहीं भूलना चाहिए जिसमें अनुशासन, टीम भावना, बलिदान, प्रतिस्पर्धा की भावना तथा विनम्र जीत व हार के अनुभव शामिल हैं। उन्होने कहा कि खेल प्रतिस्पर्धाओं की विविधता हमें सकारात्मक अवसर प्रदान करती है। खेल की चुनौतियों से जीवन की चुनौतियों पर नियंत्रण पाने की क्षमता उत्पन्न होती है जो जावन में आगे बढ़ने के लिये आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र में वर्तमान सरकार के साढ़े चार वर्षो के कार्यकाल के दौरान अभूतपूर्व विकास हुआ है और अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। उन्होने कहा कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है तथा प्रत्येक पंचायत व विधानसभा क्षेत्र का विकास करना सरकार की जिम्मेवारी है।

उन्होने कहा कि विकास की कोई सीमा नहीं होती तथा प्रत्येक दिन के बाद कुछ नया करने की ओर अग्रसर रहना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने राज्य युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह द्वारा इस प्रतियोगिता की सफलतापूर्वक मेजबानी करने के लिए सराहना की। उन्होने कहा कि विक्रमादित्य लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए नेता हैं, न कि मनोनीत हैं और हमें लोकतंत्र में विश्वास रखना चाहिए।

इस प्रतियोगिता में शिमला ग्रामीण विस क्षेत्र की 218 टीमों ने भाग लिया और इस दौरान कुल 217 मैच खेले गए। प्रतियोगिता के निर्णायक मुकाबले में करियाली टीम ने जागृति क्लब दुध धालटी की टीम को एक विकट से हरा कर विजय प्राप्त की।

प्रतियोगिता का शुभारम्भ युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह ने गत 2 अप्रैल को किया था तथा 29 दिनों तक चलने वाली इस सबसे बड़ी ग्रामीण क्रिकेट प्रतियोगिता में 2834 खिलाड़ियों ने भाग लिया।

मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किए। विजयी टीम को ट्र फी तथा एक लाख रुपये का नकद पुरस्कार जबकि उप-विजेता टीम को ट्र फी और 50 हजार रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया। उन्होने सभी प्रतिभागी टीमों को बधाई देते हुए कहा कि हार व जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन प्रतियोगिता में भाग लेना एक अहम् बात है। उन्होने महीने भर चलने वाली इस प्रतियोगिता का प्रचार करने के लिए मीडिया का आभार व्यक्त किया।

करयाली टीम के लेख राज को 'मैन आफ द मैच' के रूप में 5000 रुपये का नकद पुरस्कार तथा जागृती क्लब दुधालटी के साहिल को 'मैन आफ द टूर्नामेंट' के लिए 10 हजार रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया।

मुख्यमंत्री ने प्रतिभागियों को 'बैस्ट आल सपोंटस'(बीएएस) क्रिकेट किट वितरित की।

मुख्यमंत्री ने सुन्नी के राजकीय कालेज में हिन्दी, अंग्रेजी, वाणिज्य तथा इतिहास विषयों में स्नात्कोत्तर कक्षाएं आरम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की। उन्होने कॉलेज में स्नातक स्तर पर भुगोल तथा पत्रकारिता एवं जन संचार विषयों की कक्षाएं आरम्भ करने पर सहमति व्यक्त की।

राज्य युवा कांग्रेस अध्यक्ष व हिमाचल प्रदेश खेल, संस्कृति व पर्यावरण संघ के अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह ने इस अवसर पर कहा कि खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह का यह आयोजन पहली बार करवाया जा रहा है, जिसमें शिमला ग्रामीण विधानसभा की सभी पंचायतों की क्रिकेट टीमों को भाग लेने का अवसर मिला है। उन्होने कहा कि निकट भविष्य में क्रिकेट के अतिरिक्त फुटबाल, हॉकी, कब्बडी इत्यादि खेलों की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाएगा। इस खेल आयोजन के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रहने तथा अपने समय व ऊर्जा का सदुपयोग खेल गतिविधियों में करने का सन्देश दिया। उन्होने कहा कि भविष्य में कौशल विकास योजना के अंतर्गत कौशल विकास निगम द्वारा रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, युवाओं को स्वरोजगार के सम्भावित अवसरों के बारे भी जानकारी दी जाएगी। उन्होने कहा कि पर्यटन तथा जल क्रीड़ाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सुन्नी तथा चेवड़ी में पर्यटन केन्द्र खोलने के लिए 5 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृति की गई है। उन्होने कहा कि सुन्नी में शीघ्र ही रोजगार मेले का भी आयोजन किया जाएगा।

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इस प्रतियोगिता का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाएगा। उन्होने कहा कि प्रत्येक आयोजन को सफल बनाने में चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ युवाओं की भी जिम्मेवारी बनती है। उन्होने कहा कि बाहर से टीमें आमंत्रित करने के बजाए स्थानीय टीमों की प्रतियोगिता आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

जनता जानती है सौगातें देता कौन है और छीनता कौन

शिमला/शैल। मोदी लहर व शिमला में प्रवर्तन रैली की भीड़ से वीरभद्र सिंह और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुक्खू डर चुके हैं। भाजपा विधायकों विजय अग्निहोत्री, नरेंद्र ठाकुर एवं डा.अनिल धीमान ने सयुंक्त प्रेस विज्ञप्ति में सीएम और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पर प्रहार करते हुए यह बात कही। भाजपा नेताओं ने कहा की शिमला के रिज पर हुई ऐतिहासिक रैली में जुटी भीड़ से कांग्रेस नेताओं का मनोबल टूट गया है। यही कारण है की टूटे हुए दिल से और सामने दिखने वाली हार को झुठलाने के लिए कांग्रेस नेता पीएम नरेंद्र मोदी की आलोचना कर जनता को भ्रमित करने का असफल प्रयास करने में लगे हैं। भाजपा नेताओं ने सुक्खू के ब्यान पर पलटवार करते हुए कहा की जहां जरूरत होती है वहां पीएम छप्पन इंच का सीना बखूबी दिखाते हैं। कायरों की भांति देश के गद्दारों के साथ खड़े होने की परम्परा भाजपा की तो बिलकुल नहीं है। भाजपा नेताओं ने कहा की दशकों तक देश पर राज कर सैनिकों और शहीदों के हितों को अनदेखा करने वाली पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अपनी बिखर चुकी राजनीतिक जमीन को बंटोरने के लिए सैनिकों और शहीदों का नाम ले कर राजनीती कर रहे हैं। सीएम वीरभद्र सिंह को घेरते हुए भाजपा नेताओं ने कहा की आय से अधिक सम्पति के मामलों का अदालतों में सामना कर रहे वीरभद्र सिंह सदैव प्रो. प्रेम कुमार धूमल और अनुराग ठाकुर पर आरोप लगा कर जनता का एवं अपने शीर्ष नेतृत्व का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। जनता भली भांति है की यूपीए सरकार के तहत यह मामले दर्ज हुए थे और इन्ही मामलों की वजह से कांग्रेस हाई कमान ने वीरभद्र सिंह से पहले मंत्रालय और बाद में कैबिनेट मंत्री का पद छीना था। मुख्यमंत्री झूठ बोल कर जनता में हंसी का पात्र बन रहे हैं क्योंकि जनता जानती है की यूपीए सरकार ने प्रदेश से विशेष राज्य का दर्जा छीना था और औद्योगिक पॅकेज जो श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी ने हिमाचल को दिया था उसकी समय सीमा भी कांग्रेस की दिल्ली में चल रही सरकार ने कम की थी। कांग्रेस सरकार और संगठन के बीच की तकरार से जनता भली भांति वाकिफ है ऐसे में जब खुद सीएम सस्ती हवाई यात्रा उड़ान प्रदेश को देने के लिए पीएम का धन्यवाद कर रहे हैं तो सुक्खू इसको पीएम की देन मानने से इनकार कर रहे हैं। भाजपा नेताओं ने चुटकी लेते हुए कहा की कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष और सीएम वीरभद्र सिंह आजकल एक जुमला रटने में लगे हुए है और वह जुमला है की 'ईवीएम खराब थी'।

अधिकारी सरकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें-अनुराग ठाकुर

ऊना/शैल। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) के अध्यक्ष एवं सांसद लोकसभा अनुराग ठाकुर ने कहा कि अधिकारी सरकार की योजनाओं को धरातल तक ले जाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें ताकि योजनाओं के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा पात्र व्यक्ति लाभान्वित हो सकें। साथ ही अधिकारियों को अपने विभाग से संबंधित योजनाओं की पूरी जानकारी के साथ बैठक में आने की नसीहत भी दी ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन से लेकर उपलब्धियों बारे व्यापक चर्चा की जा सके। अनुराग ठाकुर जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

उन्होने कहा कि सरकार जरूरतमंदों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं बनाती है जिन्हें संबंधित विभागों के अधिकारी लोगों तक पहुंचाने में अपना पूरा सहयोग प्रदान करें। उन्होने कहा कि विभागीय अधिकारी लोगों के प्रति जबावदेह बनें तथा योजनाओं को पूरी निष्ठा के साथ कार्यान्वित करना सुनिश्चित बनाएं।

बैठक में मनरेगा, एनआरएलएम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सर्वशिक्षा अभियान, मध्याहन भोजन, सामाजिक सुरक्षा पैंशन, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होने बताया कि देश को 2025 तक क्षय रोग (टीबी) से मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से इस दिशा में कार्य करने का आहवान किया। उन्होने अधिकारियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर ज्यादा से ज्यादा पात्र परिवारों को लाभान्वित करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में चिंतपूर्णी अस्पताल में शवगृह बनाने के लिए स्वीकृत 30 लाख रूपये खर्च न होने का मामला उठा जिस पर विभागीय अधिकारियों ने बताया कि अस्पताल परिसर में पर्याप्त जगह न होने के कारण यह राशि खर्च नहीं हो सकी। उन्होने राशि को वापिस कर दूसरे अस्पताल में निर्मित करने के निर्देश दिए जहां इसके लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध है। उन्होने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जिला के सभी स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उन्होने बताया कि जिला में सर्व शिक्षा अभियान के तहत झुग्गी-झोंपडियों में रह रहे बच्चों के लिए जिला में 47 स्कूलों के माध्यम से लगभग 1121 बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है। जबकि विशेष बच्चों के लिए जिला में पांच विशेष चिकित्सा शिविरों के माध्यम से 15 लाख रूपये की राशि व्यय कर 509 बच्चों को लाभान्वित किया गया है। उन्होने बताया कि जिला में 772 प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों के माध्यम से 41 हजार बच्चों को दोपहर का भोजन मुहैया करवाया जा रहा है। उन्होने बताया कि जिला में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजनाओं के माध्यम से गत वित्तीय वर्ष के दौरान लगभग 76 सौ पात्रों को लाभान्वित कर लगभग आठ करोड़ रूपये की राशि व्यय की गई है। साथ ही बताया कि नंगल-तलावाड़ा रेल लाइन के निर्माण कार्य में आने वाले सात गांवों के किसानों की निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना है जिनमें से दो गांव में यह प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

बैठक में विधायक कुटलैहड़ वीरेन्द्र कंवर, कार्यकारी उपायुक्त राजेश कुमार मारिया, सहायक आयुक्त विनय मोदी, पीओ डीआरडीए राजेन्द्र गौतम, बीडीसी चेयरमैन अंब सतीश शर्मा, नगर परिषद अध्यक्ष बाबा अमरजोत सिंह बेदी, पूर्व विधायक बलवीर, संतोष सैणी, हिमोत्कर्ष संस्था के प्रदेशाध्यक्ष कंवर हरि सिंह सहित समिति के सरकारी व गैर सरकारी सदस्य उपस्थित थे।

जम्मू-कश्मीर में युवा नेताओं को शामिल करने की आवश्यकता है:ब्रिगेडियर सिसोदिया

शिमला/शैल। जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात को सुधारने के लिए वहाँ के युवा नेताओं को सकारात्मक तरीकों से संलग्न करने की आवश्यकता है। यह कहना है, 26/11 के हमलों के दौरान होटल ताज और ट्राइडेंट में एन. एस.जी के सफल आतंकवादी विरोधी अभियानों का नेतृत्व करने वाले अधिकारी ब्रिगेडियर गोविंद सिंह सिसोदिया का। ब्रिगेडियर सिसोदिया, जो की भारतीय फौज में अधिकारी रह चुके हैं, ने यह बात शूलिनी विश्वविद्यालय में आयोजित 'गुरु सीरीज लैक्चर' के दौरान कही।

शिमला की चौपाल तहसील से संबंध रखने वाले ब्रिगेडियर सिसोदिया एक जाने माने सुरक्षा विशेषज्ञ है। सेना और एनएसजी के अलावा, वह राष्ट्रमंडल खेलों के लिए इंटरनेशनल सिक्योरिटी ग्रुप के सदस्य भी रह चुके हैं। वह भारतीय क्रिकेट टीम के लिए सुरक्षा सलाहकार के रूप में भी बीसीसीआई से जुड़े थे।

वर्ष 2008 के नवंबर 26 के महत्वपूर्ण दिन का स्मरण करते हुए ब्रिगेडियर सिसोदिया ने कहा कि मुंबई में उस दिन बहुत अस्तव्यस्तता थी। सामान्य धारणा के विपरीत, ब्रिगेडियर सिसोदिया मीडिया को उस दिन की कवरेज के लिए काफी श्रेय देते हैं। उनके अनुसार मीडिया द्वारा दी गई कवरेज से पूरे देश में देशभक्ति चरम पर थी और सब एकजुट थे, जिससे आतंकवादियों के खिलाफ कारवाई करने वाली टीम का मनोबल और बढ़ गया। मीडिया कवरेज की वजह से ही पूरी दुनिया ने देखा की हमारे देश में क्या हो रहा है और आखिरकार पाकिस्तान पर दबाव बनने लगा।

कश्मीर की वर्तमान स्थिति पर ब्रिगेडियर सिसोदिया, जिन्होनें खुद कश्मीर घाटी में काफी समय बिताया है का कहना था कि अभी तक सरकार ने राजनेताओं और अलगाववादियों के जरिये ही प्रयास किए हैं लेकिन यह लोगों, खासतौर पर युवाओं को अपने साथ जोड़ने में विफल रहे हैं। उनके अनुसार सरकार को युवा नेताओं को सकारात्मक तरीके से अपने प्रयासों में शामिल करना चाहिए।

उन्होंने छात्रों के समक्ष सेना के विभिन्न पहलू पर अपने विचार रखे। उन्होनें सशस्त्र बलों के नेतृत्व को उजागर करते हुए 26/11 आपरेशन में शामिल बहादुर सैनिकों की देश के प्रति निस्वार्थ भावना का वर्णन करते हुए बताया कि कैसे उन वीरों ने अपनी टीम और निर्दोष नागरिकों के जीवन को बचाया।

ब्रिगेडियर सिसोदिया ने भारतीय क्रिकेट टीम के सुरक्षा सलाहकार के रूप में सामने आई चुनौतियों के बारे में भी बताया। विद्यार्थियों के लिए उनकी सलाह थी कि वह नवाचार और पहल जीवन के एक अभिन्न अंग हैं, इसलिए अपनी आंखों और कानों को खोलें और अपनी उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित रखें।

इस अवसर पर शूलिनी विवि के उप कुलपति प्रोफेसर पी.के. खोसला ने कहा कि ब्रिगेडियर सिसोदिया जैसी व्यक्तित्व वाले इंसान से भारतीय सेना और उसके नेतृत्व करने के ढंग को जानकार छात्रों में अवश्य ही फौज के प्रति समान्न और बढ़ा होगा। उन्होंने कहा कि इस व्याख्यान से निश्चित रूप से छात्रों को नेतृत्व की बारीकियों को सीखने में मदद करेगा। इस मौके पर विश्वविद्यालय के वरिष्ठ सदस्यों के अलावा, छात्र और संकाय मौजूद रहे।

स्वच्छता अभियान के दौरान समस्त जल स्त्रोतों को स्वच्छ रखने के निर्देश:मुख्यसचिव

शिमला/शैल। मुख्य सचिव वी. सी. फारका ने सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग को स्वच्छता अभियान के दौरान नदी-नालों व जलापूर्ति योजनाओं के समस्त जल स्त्रोंतों को स्वच्छ रखने के निर्देश दिए। यह अभियान राज्य में जिला प्रशासन के सौजन्य से पंचायती राज संस्थानों, विभागीय कर्मचारियों व आम जनमानस के सहयोग से 2 मई से 5 मई, 2017 तक चलाया जाएगा।

फारका ने ये निर्देश राज्य में गर्मियों के दौरान सूखे जैसी स्थिति की समीक्षा करते हुए सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं के साथ वीडियो कान्फ्रेन्सिग के माध्यम से दिए।

उन्होंने कहा कि भण्डारण टेंकों की सफाई सुनिश्चित बनाई जानी चाहिए और इस पर सफाई करने की तिथि भी अंकित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सूचना, शिक्षा व संप्रेषण गतिविधियों के माध्यम से पानी को पीने योग्य बनाने तथा जल जनित रोगों से बचने व पानी की महता के बारे लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। उन्होंने सभी मुरम्मत योग्य हैण्ड पम्पों को शीघ्रातिशीघ्र क्रियाशील बनाने को कहा और जिनकी मुरम्मत संभव नहीं हैं, उन्हें कारणों सहित बंद करने को कहा।

मुख्य सचिव ने मुख्य पाईप लाईन तथा ग्रेविटी लाईन से निजी कनेक्शन न देना सुनिश्चित बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में यदि इस प्रकार के कनेक्शन हैं तो उन्हें तत्काल काट दिया जाना चाहिए। उन्होंने सभी लोगों को बराबर जल आपूर्ति सुनिश्चित बनाने को कहा।

मुख्य अभियंताओं ने जानकारी दी कि प्रदेश में कुल 9393 जलापूर्ति योजनाओं में से वर्तमान में स्त्रोंतों में पानी की कमी के कारण 119 योजनाएं आंशिक रूप से बाधित हैं। वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है तथा किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिये विभाग तैयार है। विभाग ने सुचारू जलापूर्ति के लिये राज्य में 3568 हैण्डपंप स्थापित किए हैं।

लैन्टाना प्रबन्धन के लिए सरकार ने बनाई नई नीति

शिमला/शैल। वन एवं मत्स्य मंत्री हि. प्र. ठाकुर सिंह भरमौरी, ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश की वन व बन्जर भूमि पर लैन्टाना तेजी से फैल रहा है जिसके कारण जैव विविधता पर नकारात्मक असर हो रहा है। वन विभाग द्वारा वर्ष 2010-11 और वर्ष 2015-16 में लैन्टाना से प्रभावित वन भूमि का प्रदेश में वन मण्डल स्तर पर सर्वेक्षण किया गया और यह पाया गया कि प्रदेश की 2,35,491.43 हैक्टेयर वन भूमि लैन्टाना से प्रभावित है। इस समस्या के समाधान के लिए प्रदेश सरकार ने नई लैन्टाना प्रबन्धन नीति घोषित की है जिसका उद्देश्य लोगों को लैन्टाना उन्मूलन के लिए प्रेरित करना व लैन्टाना आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना है। हिमाचल प्रदेश वन विभाग ने पहले भी राज्य कैम्पा फंड के तहत लैन्टाना उन्मूलन के प्रयास किए हैं। इस नई लैन्टाना प्रबन्धन नीति का लक्ष्य लैन्टाना प्रभावित भूमि से लैन्टाना हटाकर पुनः स्थापित कर चारा प्रजातियों को बढ़ावा देना है तथा स्थानीय लोगों, युवक मण्डलों, महिला मण्डलों गैर सरकारी संगठनों और उद्योगपतियों को शामिल करके उन्हें आर्थिक लाभ पहुंचाना है। लैन्टाना उन्मूलन का कार्य 1 नवम्बर से 31 जनवरी तक किया जाएगा। इस नीति की विस्तृत जानकारी नेट पर उपल्बध है।

सतत् जल विद्युत के लिए जलागम उपचार पर परामर्श गोष्ठी आयोजित

शिमला/शैल। जल विद्युत परियोजनाओं से पर्यावरण खराब होता है। यह कहना गलत है। यह शब्द तरुण कपूर प्रधान सचिव वन ने सतत् जल विद्युत के लिए जलागम उपचार (catchment treatment for sustainable hydroelectric project) पर आयोजित परामर्श गोष्ठी के दौरान कहे। होली डे होम शिमला में आयोजित इस गोष्ठी का आयोजन सभी हिस्सेदार विभागों अथवा संस्थाओं के साथ मिलकर किया गया। तरुण कपूर ने कहा कि जल विद्युत परियोजनाओं की लोग अकसर आलोचना करते हैं कि उनसे पर्यावरण को नुकसान होता है, बल्कि उनके अनुसार ऐसा नहीं है, इससे परियोजनाओं के आस-पास के स्थानों पर बदलाव आता है। यह बदलाव वहां रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति को लेकर, वहां के स्थानों पर परियोजना द्वारा उपलब्ध करवाए धन से किए कार्यों द्वारा देखा जा सकता है। उनके अनुसार परियोजना कार्यों से छोटे-छोटे जल स्त्रोतों का ही निर्माण कार्य नहीं किया जाता, परन्तु पौधरोपण के कार्य भी किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि सतलुज जलागम क्षेत्र में बहुत सी परियोजनाएं लगाई गई, जिनसे क्षेत्र में किए गए पौधरोपण तथा अन्य कार्य देखे जा सकते हैं तथा लोगों की आर्थिक स्थिति में आए बदलाव को भी देखा जा सकता है। उनके अनुसार यह परियोजनाएं लम्बी अवधि तक चलती हैं तथा वहां से अर्जित धन विकासात्मक कार्यों में लगाया जाता है, जिससे पर्यावरण पर नकारात्मक नहीं अपितु सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

भरमौरी और केवल पठानिया का प्रबन्धन सवालों में विभाग को लगी 60 करोड़ की चपत कैग में हुआ खुलासा

शिमला/शैल। विधानसभा पटल पर रखी कैग रिपोर्ट खुलासे के मुताबिक वन विभाग और वन निगम के प्रबन्धन के कारण सरकारी खजाने को करीब 60 करोड़ की चपत लगी है। वन महकमे के मन्त्री ठाकुर सिंह भरमौरी और वन निगम के उपाध्यक्ष केवल सिंह पठानिया दोनो ही मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह के अति विश्वस्त माने जाते है। इसी कारण पठानिया का दखल विभाग मे भी विशेष चर्चा का विषय बना हुआ है। कैग रिपोर्ट के परिणामों के आधार पर संबधित अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला तक दर्ज किया जा सकता है ऐसा एग्रो पैकेजिंग कारपोरेशन के केस में भी हो चुका है, लेकिन आज विभाग और निगम का राजनीतिक नेतृत्व मुख्यमन्त्री के खास लाडलों के पास है इसलिये इस तरह का कड़ा कदम नही उठाया जायेगा यह तय है। फिर भी कैग का खुलासा पाठकों के सामने रखा जा रहा है।

वनों के उत्पादन, प्रबन्धन और संरक्षण की जिम्मेदारी वन विभाग के पास है, लेकिन वन उपज के दोहन की जिम्मेदारी वन विभाग के पास है। वन उपज के दोहन के लिये संबधित वन क्षेत्र को एक तय समय सीमा तक निगम को लीज पर दिया जाता है। वन उपज के दोहन के लिये पेड़ कटान आदि हर चीज के रेट निर्धारित करने के लिये एक प्राईसिंग कमेटी बनी हुई है। मई 2011 में इस कमेटी ने तय किया था कि वन उपज के लिये प्रदेश के हर कोने में एक समान रेट लागू होंगे। 1991 में विभाग ने यह निर्देश जारी किये थे कि जो वनभूमि गैर वन उपयोग के लिये आवंटित की जायेगी उस पर पाये जाने वाले वृक्षों की कीमत संबधित ऐजैन्सी से ली जायेगी। 2004 में ब्लॉक अधिकारियों और रेंज अधिकारियों को पीसीसीएफ की ओर से निर्देश जारी किये गये थे कि अपने-अपने क्षेत्र का नियमित दौरा करें और यदि किसी तरह का कोई अवैध कटान सामने आता है तो उसकी तुरन्त रिपोर्ट करके अगली कारवाई को अन्जाम दें। ऐसे मामलों में पुलिस में भी समानान्तर कारवाई करके एफआईआर दर्ज करने का भी प्रावधान है। अवैध कटान आदि के मामलों में जब्त की गयी लकड़ी को तुरन्त सुपुर्ददारी में लेकर उसकी सुरक्षा करना और फिर उसकी निलामी आदि का प्रबन्ध करना फॉरेस्ट एक्ट 1951 की धारा 52 में पहले से ही दर्ज है।

इस तरह प्रबन्धन की जिम्मेदारी है कि रायल्टी की उगाही या उसके आकलन के कारण विभाग को राजस्व का नुकसान न हो। रायल्टी के साथ ही यह भी सुनिश्चित करना प्रबन्धन की जिम्मेदारी होती है कि यदि लीज अवधि के अन्दर काम पूरा नही हो सका है और उसके लिये समय सीमा बढ़ाई गयी है उसके लिये फीस ली जानी होती है। जब्त की गयी लकड़ी की समय पर निलामी सुनिश्चित करना यह सब कुछ विभाग के प्रशासकीय दायित्वों का एक बहुत अहम भाग है। विभाग के शीर्ष प्रबन्धन और राजनीतिक नेतृत्व की यह जिम्मेदारी है कि वह देखे कि विभाग के

कर्मचारी/अधिकारी इन दायित्वों को ईमानदारी से निभा रहे है या नहीं। जब यह दायित्व नहीं निभाने के कारण सरकारी राजस्व को हानि पहुंचाई जाती है और उसके लिये किसी को भी जिम्मेदार नही ठहराया जाता है तब उस स्थिति को जंगलराज की संज्ञा दी जाती है। इस जंगल राज के कारण आनी, बिलासपुर, देहरा, किन्नौर, करसोग, मण्डी, नाचन, रेणुकाजी, सिराज, शिमला, सोलन और ठियोग मण्डलों में जब्त की गई लकड़ी की निलामी न किये जाने के कारण अब तक 6.94 करोड़ के राजस्व का नुकसान हो चुका है। विभाग ने 2011 से 2015 के बीच वन निगम को 57488.75 घन मीटर लकड़ी की निकासी का काम सौंपा। इसमें विभाग की 2011 की प्राइसिंग कमेटी के अनुसार रायल्टी का आकलन न करने के कारण 8.30 करोड़ के राजस्व की हानि हुई है। गैर वन उपयोग के लिये किन्नौर में 20 मैगावाट के राओरा हाईड्रो पावर को दी गयी जमीन पर खड़े 536 पेड़ो की कीमत प्रोजेक्ट से न वसूलने के कारण 32.50 लाख का नुकसान हुआ है। इसी तरह ईइनसी भवन शिमला, छोटा शिमला कार पार्किंग निर्माण और लोक निर्माण विभाग को एवर सन्नी, गोलचा- भौंट सकड़ निर्माण के लिये दी गयी वन भूमि के एवज में यूजर ऐजैन्सी से 50.70 लाख नही वसूले गये। सिराज में 2008 से 2015 के बीच 36 लॉटस दोहन के लिये निगम को दिये गये जिनमें 17. 20 लाख की एक्सटैंशन फीस नही वसूली। इसी तरह चुराह में 91 पेड़ो के अवैध कटान की कोई डैमेज रिपोर्ट तक नही काटी गयी और न ही कोई एफआईआर दर्ज करवायी गयी। इससे करीब एक लाख का नुकसान हुआ। इन मामलों का कैग ने गंभीर संज्ञान लिया है लेकिन सरकार के स्तर पर कहीं कोई कारवाई नहीं है।

शीर्ष प्रशासन की खामोशी के बाद अदालत के नोटिस पर हुई जे.पी.के छः अफसरों के खिलाफ एफ आई आर

शिमला/शैल। सरकार, शासन व पुलिस के आलवा कांग्रेस व भाजपा के लाडले सीमेंट कारोबारी जे पी कंपनी के छह अफसरों के नाम अर्की की नीचली अदालत की ओर से केवल नोटिस भेजने पर ही एफआईआर में शामिल कर लिए गए हैं। ये नोटिस ज्यूडिशियल मेजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अर्की की ओर से लक्ष्मी चंद की अर्जी की सुनवाई पर दिए गए थे।

अर्की की तहसील के मांगल में एक शख्स की जमीन व मकान को कब्जे में लेने के लिए जे पी कंपनी के अफसरों ने 20 फरवरी 2017 को ब्लास्टिंग की तरकीब निकाली थी व गांव बागा डंगोली के लक्ष्मी चंद शर्मा ने इस बावत थाना बागा, एसपी व वीरभद्र सरकार के गृह सचिव प्रबोध सक्सेना से भी जे पी कंपनी के अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आग्रह किया था। चूंकि मामला जे पी कंपनी जैसे बड़े कारोबारी का था तो किसी ने कुछ नहीं किया।

बहरहाल, लक्ष्मीचंद ने अर्की की अदालत ने अर्जी दाखिल कर दी व अदालत से एफआईआर दर्ज कराने का आदेश देने का आग्रह किया। अदालत की ओर से नोटिस देकर रिपोर्ट मंगवाने पर पुलिस ने धारा 436, 295, 295, 341, 506 के तहत दर्ज एफआईआर में कंपनी के टॉप कर्ताधर्ताओं निदेशक रणविजय, जे शेरू, आर पी गौतम, मुकेश शर्मा, ब्लास्टिंग प्रभारी आर के पाठक और पी विक्रम के नाम शामिल कर दिए हैं।

पुलिस ने नोटिस मिलने के तुरंत बाद ही लक्ष्मीचंद के ब्यान भी दर्ज कर लिए है।

यह है मामला जिस जमीन को जे पी कंपनी कब्जे में लेना चाहती है उसका अवार्ड 2008 में हो चुका है लेकिन लक्ष्मी चंद को कहीं पुन र्विस्थापित नहीं किया गया व उससे कब्जा भी नहीं लिया गया था।

जेपी कंपनी ने बीच में इस जमीन व पूजा स्थल का कब्जा लेने की कोशिश भी की लेकिन विरोध के बाद वो ऐसा नहीं कर पाया। तब कंपनी के अफसरों ने ब्लास्टिंग की तरकीब निकाली व इससे पूजा स्थल व रास्ते में पत्थर आ गए व रास्ता ब्लॉक हो गया। इससे लक्ष्मी चंद का पूजा स्थल तक आना जाना बाधित हुआ । थाना बागा में 21 फरवरी को दी शिकायत में लक्ष्मीचंद ने ये भी कहा कि उसे कंपनी के कर्ताधर्ताओं ने धमकाया भी। बहरहाल, पुलिस मौके पर गई लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की।

इसके बाद मामला गृह सचिव प्रबोध सक्सेना तक गया पर सरकार ने तब भी एफआईआर दर्ज नहीं की हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखे है कि एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए।

उधर, मजेदार ये है कि इस मामले में कांग्रेस व भाजपा के नेताओं की जुबान नहीं खुलती हैं जबकि दोनों सता व विपक्ष में हैं। अब तो यूं भी चुनाव को दौर चलने वाला है।

सर्वोच्च न्यायालय से अनुराग ठाकुर को राहत

शिमला/शैल। सर्वोच्च न्यायलय ने सांसद अनुराग ठाकुर, संजय शर्मा, गौतम ठाकुर, एचपीसीए और अन्य लोगों को राहत देते हुए हिमाचल हाई कोर्ट के उस फैसले पे स्टे दे दिया है, जिसमे हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ दायर एफआईआर रद्द करने से मना कर दिया था। इस मामले एचपीसीए की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को वैयक्तिक रूप से नोटिस जारी करते हुए उन्हें हलफनामा दायर कर अगली सुनवाई से पहले जवाब देने के लिए कहा है। एचपीसीए ने अपनी याचिका में आरोप लगाया की यह मामला राजनीति से प्रेरित है और मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के शह पर यह मामला दाखिल हुआ है। इसका संज्ञान लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री को अगली सुनवाई से पहले जवाब दाखिल करने को कहा है।

यह मामला एचपीसीए द्वारा कथित तौर पर शिक्षा विभाग की 720 स्क्वायर मीटर जमीन पर अतिक्रमण करने का था। इस एफआईआर के खिलाफ एचपीसीए ने हिमाचल हाईकोर्ट में अपील कर इसे रद्द करने की मांग कि थी, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ अनुराग ठाकुर और अन्य लोग सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। न्यायाधीश ए के सिकरी और अशोक भूषण के पीठ ने सुनवाई करते हुए हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को स्टे देते हुए, निचली अदालत में चल रहे सुनवाई पर भी स्टे किया है और हिमाचल प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को वैयक्तिक रूप से हलफनामा दाखिल कर जवाब देने के लिए कहा है। इस मामले कि अगली सुनवाई अगस्त में होगी और तब तक इस मामले पर निचली अदालत में जारी सुनवाई पर स्टे जारी रहेगा।

मुख्यमन्त्री द्वारा 18 पत्र .....पृष्ठ 1 का शेष

कहकर कि युवा कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनावों में जीतने वाले युवाओं को टिकट देने की सिफारिश करेगी, अपना कद बढ़ा हुआ दर्शाने का प्रयास किया।

प्रदेश भाजपा के नेताओं धूमल व नडडा के इन दावों को कि मोदी सरकार ने प्रदेश को 60 से ज्यादा नेशनल हाईवे दिए हैं को नकार दिया व कहा कि उनके पिता व सीएम वीरभद्र सिंह ने 6 मई 2016 से 27 अक्तूबर तक मोदी सरकार को 18 चिट्ठियां लिखी तब जाकर ये एनएच मिले लेकिन 59 एनएच में से अभी तक केवल दस एन एच की डीपीआर को सैद्धातिक मंजूरी मिली है, जबकि डीपीआर के लिए मिलने वाले 200 करोड़ में से एक भी पैसा नहीं मिला हैं।

सीएम वीरभद्र सिंह, उनके पुत्र व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल व उनके लाडलों ने एक अरसे से एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलने का अभियान छेड़ा हुआ हैं। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए वीरभद्र के पुत्र ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम वीरभद्र को लेकर कहा कि वो अपना सारा समय वकीलों संग बिताते हैं। लेकिन एक नया सर्वे आया है जिसमें हिमाचल को सबसे कम भ्रष्टाचार वाला राज्य पाया गया है। ऐसे में धूमल सरकार में जो हजारों करोड़ों की जमीन हथिया ली वो बड़ा भ्रष्टाचार नहीं है। ये मामले अदालतों में चल रहे हैं।